Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

छठा सप्रु हाउस व्याख्यान

द्वारा

महामहिम श्री फेम बिन्ह मिन्ह

सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ वियतनाम के विदेश मंत्री

विषय

"भारत वियतनाम संबंध और क्षेत्री मुद्दे"

स्थान
सप्रु हाउस, नई दिल्ली

12 जुलाई, 2013

राजदूत श्री राजीव कुमार भाटिया, सभापति, देवियों और सज्जनों,

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्- एक प्रतिष्ठित संस्था में आपके साथ होना बड़े गौरव की बात है। यहां खड़े होकर मुझे दिवंगत प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू , जिन्होंने इस भवन की स्थापना की और दिवंगत राष्ट्रपति हो ची मिन्ह, जो कुछ दशक पूर्व भारत दौरे के दौरान यहां थे, का स्मरण कर रहा हूं। अंकल हो और चाचा नेहरू हमारे दो महान संस्थापकों ने वियतनाम और भारत के बीच साझा संबंध की नींव रखी थी।उनकी गर्मजोशी भरी व्यक्तिगत दोस्ती ने हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध को मजबूत बनाने में सहायता की। अपने कार्यकाल के दौरान दिवंगत राष्ट्रपति हो ची मिन्ह ने एशिया और विश्व में शांति स्थापना के लिए प्राय भारत- एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र- द्वारा दिए गए योगदान पर जोर दिया। ये सभी शब्द आज भी प्रासंगिक हैं।

इसके अतिरिक्त मैं हमारे दो देशों के बीच इस वार्ता और समझ को मजबूत करने के लिए राजदूत राजीव भाटिया और विदेशी मामलों की भारतीय परिषद् को धन्यवाद देना चाहूंगा। वियतनाम की कूटनीतिक अकादमी के साथ आपके संयुक्त प्रयास ने गत जुलाई में *वियतनाम और भारत रणनीतिक साझेदारी: भावी दिशानिर्देश* संबंधी सेमीनार को संभव बनाया। मुझे यह जानकारी दी गयी कि उक्त सेमीनार बड़ा सफल रहा।

देवियों और सज्जनों, तथ्य यह है कि मुझे आज अपने द्विपक्षीय संबंध में वियतनाम में आपके हितों के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है कि हमारे दोनों देश किस प्रकार इस बदलती दुनिया और क्षेत्रीय परिदृश्य में साथ मिलकर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।

इस अवसर पर मैं अपनी दुनिया और अपने क्षेत्र की गतिशीलता , भारत, आसियान और वियतनाम की भूमिकापर कुछ विचारों को साझा करने और हमारी भावी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सुझाव देना चाहता हूं।

1. वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ

सर्वप्रथम मैं प्राय: स्वयं से पूछता हूं: अभी हम किस प्रकार की दुनिया में रह रहे हैं?

पिछले कुछ वर्षों से मुझे प्रतीत होता है कि हम एक ऐसी दुनिया के समक्ष हैं जो पूरी तरह से बदल गयी है। वैश्विक वित्तीय संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्थामें , विकास मॉडल और रणनीतियों में , निर्माण, उपभोक्ता और वित्तीय बाजारों की प्रवृत्ति में तथा अर्थव्यवस्थाओं व क्षेत्रों की बढ़ते संपर्क में ढ़ांचागत परिवर्तन ला दिया है।

इन बदलावों का तत्काल एक प्रभाव शक्ति की गतिशीलता में परिवर्तन है। हमने देखा है कि

शक्तियां धीरे-धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर , उत्तर से दक्षिण की ओर और विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर परिवर्तित हो रही हैं। जहां अग्रणी औद्योगिक शक्तियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वहीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रकट रूप से अविराम उत्थान दिखा है। केवल विगत पांच वर्षों में ही वैश्विक आर्थिक शक्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। वर्ष 2010 में चीन विश्व का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है , वर्ष 2011 में भारत नौंवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी एवं ब्राजील तो पहले ही ब्रिटेन के बराबर आ गया है। 2001 और 2012 के बीच ब्रिक्स अर्थव्यवस्था का कुल आकार छह गुणा बढ़ गया है जबकि विश्व की समग्र अर्थव्यवस्था दोगुनी बढ़ गयी है। ब्रिक्स की आवाज को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था , अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक सुरक्षा ढ़ांचे में उत्तरोत्तर सुनी जा रही है। जी-20 की समन्वित आर्थिक भूमिका भी एक स्थापित तथ्य है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने राजनीतिक शक्तियों की प्रवृत्ति को पूरी तरह से बदल दिया है। प्रमुख शक्तियों के बीच संबंध अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों का विशेष क्षेत्र नहीं रहा है।

इस पृष्ठभूमि में हमारा एशिया अब गुरूत्वाकर्षण , वैश्विक विकास और आर्थिक लाभ का केन्द्र बन रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक मंदी के होते हुए भी एशियाई अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत वृद्धि दर्ज किए हुए है। पिछले वर्ष यह विकास दर 7.6 प्रतिशत तक पहुंच गयी। एशिया की एक उल्लेखनीय विशेषता उभरता क्षेत्रवाद है। कुल 76 मुक्त व्यापार समझौतों के साथ एशिया-प्रशांत क्षेत्र दोहा दौर की प्रगति के न होने पर आर्थिक एकीकरण के अभियान में विश्व की अगुवाई की। मेरा विचार है कि कई एफटीए और आर्थिक संबद्धता के अन्य रूपों का विकास होना जारी रहेगा। उदाहरण के लिए , आसियान समुदाय की प्रक्रिया के साथ साथ हमने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) , ट्रांस पैसेफिक साझेदारी (टीपीपी) , पूर्वोत्तर एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान और अमेरिका के बीच संवर्धित आर्थिक अनुबंध, मेकोंग सुरीजनल कॉपरेशन को धीरे-धीरे उभरते देखा है। अब आसेम (एएसईएम) और एपेक (एपीईसी) के बीच क्रियाकलापों का कार्यक्षेत्र गैर परंपरागत मुद्दों को शामिल करने के लिए बढ़ रहा है।

एशिया के महत्व का एक और संकेत यह है कि सभी प्रमुख शक्तियां अब इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कररही हैं। यह अपरिहार्य है क्योंकि चार प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं ,संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्य और जी 20 के 20 सदस्यों में से 10 सदस्य एशिया से हैं। दुनिया चीन के शानदार उत्थान, अमेरिका की अपनी पुनर्संतुलन रणनीति, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति और जापान द्वारा धीरे-धीरे एक सक्रिय भूमिका में आने पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। कई प्रमुख थिंक टैंक इस बात से सहमत हैं कि 2030 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र शक्ति, जनसंख्या, जीडीपी आउटपुट और सैन्य खर्च के मामले में अन्य महाद्वीपों और क्षेत्रों को पीछे छोड़ देगा।

इन गहन परिवर्तनों ने अवसरों और चुनौतियों दोनों को जन्म दिया है। हालांकि प्रमुख शक्तियां

अभी भी घटनाओं को नियंत्रित करने की अपनी विशाल क्षमता को बरकरार रखी हुई हैं , लेकिन उभरती शक्तियों के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय राजनीति अधिक लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीय हो गई है। यदि हम एक दशक पहले वैश्विक परिदृश्य पर विचार करें , तो हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठन आज शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभारहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून को अब सभी वैश्विक मुद्दों के संदर्भ के रूप में मान्यता दी गई है।इस प्रकारविकास के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करते हुए इस पृष्ठभूमि मेंशांति और स्थिरता को बनाए रखने की अधिक संभावना है। औरबदले में एक समृद्ध एशियाहमारे प्रत्येक देश में सामाजिकआर-ंथिक विकास के लिए बहुत प्रेरक है।

हालांकि, ऐतिहासिक रूप सेसत्ता की गतिशीलता में कोई बदलाव एक प्रकार की अराजकता की ओर ले जाता है। एशिया के देशों को अभी भी इराक और अफगानिस्तान में युद्धों के परिणाम के साथ-साथ आतंकवाद की भयावह छाया से जूझना पड़ रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। आज आंशिक रूप से आर्थिक मंदी के कारण हमें आंतरिक आर्थिक , राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गैर-पारंपरिक खतरे यथा जलवायु परिवर्तन , समुद्री उदय, आपदाओं, खाद्य, ऊर्जा और जल सुरक्षा , साइबर क्राइम आदि अब हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं।विशेष रूप से चिंता का विषय देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद हैं , विशेषकर पूर्वी चीन सागर और पूर्वी सागर (दक्षिण चीन सागर)। इन विवादों ने प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा , रणनीतिक लक्ष्यों में परिवर्तन, बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हथियारों की दौड़ को और गंभीर बना दिया है।

इन सभी जटिलताओं के बीचहम सभी का शांति , स्थिरता, सुरक्षा और प्रमुख समुद्री मार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता में साझा हित हैंजो पश्चिम और पूर्व को, भूमध्य सागर से, हिंद महासागर से होते हुए से खाड़ी, पूर्वी सागर को और आगे प्रशांत को जोड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाओं ने पूर्वी सागर में स्थिति को जटिल बना दिया है, जो उस समुद्री मार्ग के सबसे महत्वपूर्ण लिंक में से एक है। मेरा मानना है कि भारत के लोग उन घटनाओं से अवगत हैं।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वैश्विकसाझेदारी के लिए पूर्वी सागर का अत्यधिक महत्व है यानी समग्र शांति -, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता और पूरी दुनिया की समृद्धिके लिए। यह अनुमान है कि वस्तु व्यापार में तीन चौथाई से अधिक वैश्विक व्यापार समुद्र-द्वारा ले जाया जाता हैऔर इसमें से दो तिहाई-वस्तुओं को माल पूर्वी सागर के रास्ते ले जाया जाता है। पूर्वी सागरके तटीय राष्ट्र और सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, जोइस क्षेत्र के अंतर्गत या इसके बाहर आते हैं, सभी समुद्री क्षेत्र अपनी आजीविका के लिए इस समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। इसी कारण से प्रत्येक देश की विरासत की रक्षा करने के अलावाहमें इन वैश्विक साझा विरासतों ,जो संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, और प्राकृतिक संसाधनों, मत्स्य पालन और तेल के संदर्भ मेंहै , आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी प्रयास

करना चाहिए।

सिंगापुर में पिछले महीने 12 वें शांगरी-ला संवाद में, वियतनाम के प्रधान मंत्री गुयेन टैन डंग ने सभी देशों को संयुक्त रूप से शांति , सहयोग और समृद्धि के लिए रणनीतिक विश्वास बढ़ाने का आह्वान किया। यह रणनीतिक विश्वास सद्भावना और ईमानदारी , अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की इच्छा और सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी , प्रमुख शक्तियों का पहला और महत्वपूर्ण आधार पर होना चाहिए। और बहुपक्षीय सुरक्षा तंत्र की दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिए , जिसमें आसियान की केंद्रीयता का सम्मान किया जाना चाहिए।

इस संबंध में , हम उच्च समुद्र के साथ-साथ पूर्वी सागर पर समुद्री लेनों में शांति बनाए रखने और सुरक्षित करने के मुद्दे पर शब्दों में और कर्मों में भारत गणराज्य की सुसंगत स्थिति की सराहना करते हैं। हम पिछले दिनों ब्रुनेई में आसियान के साथ बैठक के दौरान विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के हालिया बयान का स्वागत करते हैं , जब उन्होंने बल के किसी भी उपयोग को अस्वीकार कर दिया और नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया।

आखिरकार, मेरे मित्र, जैसा कि जवाहर लाल नेहरू ने कहा: "*शांति के बिना, अन्य सभी सपने टूट जाते हैं और वह राख में बदल जाते हैं।*"

2. *क्षेत्रीय संरचना, भारत और आसियान की भूमिका*

देवियों और सज्जनों,

दूसरा प्रश्न जिस पर मैं स्वयं चिंतन कर रहा हूं: हम इस अपरिचित जल क्षेत्र में कैसे नौवहन करें?हम शांति और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक आधार का निर्माण करते हैं , ताकि हम सभी एशिया में समृद्ध हो सकते हैं?

मेरा विचार है कि शांति की गारंटी अकेले रक्षा साधनों से नहीं दी जा सकती है। शांति का जवाब आर्थिक, व्यापार, राजनीतिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों की समग्र कनेक्टिविटी और लिंकेज में देशों के निरंतर विस्तार वाले नेटवर्क में निहित हो सकता है। हमें न केवल देशों के बीच, बल्कि विभिन्न स्तरों पर भी ऐसा करना चाहिए: उप-क्षेत्रों, अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर। इस गहन एकीकरण के द्वाराहम अंतःनिहित हितों का सृजन कर सकते हैं , सभी देशों को शामिल कर सकते हैं , नियमों और मानदंडों को लागू कर सकते हैं और संघर्ष की संभावनाओं को कम कर सकते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुएमुझे लगता है कि हमें एक व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि एशिया - प्रशांत और दक्षिण एशिया अंतर्संबंधित है जिसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। आज कई ऐसे

प्रस्ताव, विचार, अवधारणाएं और पहल हैं जो पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ दक्षिण एशिया के बीच संबंध को बढ़ावा देती हैं। यह एक वास्तविकता को दर्शाता है कि हम सभी एक समान समृद्धि को साझा करते हैं, हमारे भाग्य परस्पर जुड़े हुए हैं। और आसियान हमारे क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो भारत के लिए एशिया - प्रशांत के प्रवेश द्वार के रूप में है।

जैसा कि आप जानते हैं, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था संघर्षों को रोकने और प्रबंधित करने में पूरी तरह से प्रभावी नहीं रही है, और न ही वे 2003 में एसएआरएसप्रकोप, 2004 मेंहिंद महासागर में और 2011 में जापान में सुनामी आपदाओं जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों से पर्याप्त रूप से निपटते हैं।

इसलिए , चुनौतियों के समाधान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को साकार करने की दिशा में एक कदम के रूप में विकसित क्षेत्रीय संरचना की अपेक्षा की गई है। उस रेखा के साथआसियान ने क्षेत्रवाद संधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संघ 600 मिलियन उपभोक्ताओं और 2 ,100 बिलियन अमरीकी डालर जीडीपी आउट वाले आर्थिक समुदाय की गतिशील वृद्धिको बनाए रखने में सक्षम है। अधिकांश क्षेत्रीय और द्विपक्षीय एफटीए का केंद्र होने के अलावा, आसियान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के तंत्र और माध्यम का भी केन्द्र है। मैं दक्षिण चीन सागर (डीओसी) , पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), आसियान+ रक्षा मंत्रियों की बैठक में विभिन्न देशों की संहिता की घोषणा, एमिटी एंड कोऑपरेशन (टीएसी) संबंधी संधि, एसईएनडब्ल्यूएफजेडका नाम ले सकता हूं। आसियान की वार्षिक सभाएं सभी क्षेत्रीय देशों को एक साथ आने, संभावित संघर्षों का प्रबंधन करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक मंच प्रदान करती हैं। अब तक, आसियान सभी संवाद भागीदारों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने में एक गतिशील संतुलन बनाए रखने में सक्षम रहा है।

आगामी वर्षों मेंआसियान की प्राथमिकताएं हैं: 2015 के अंत तक एक समुदाय के प्रति रोडमैप को महसूस करना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना और विकास खाई को पाटनातथा सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना। तथापि,2015 से आगे बढ़ते हुएआसियान को क्षेत्रीय संरचना को विकसित करने में हमारी केंद्रीयता बढ़ाने में अधिक सक्रिय होना चाहिए। हमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा दोनों मुद्दों पर इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख चुनौतियों को दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

इन लक्ष्यों को महसूस करने के लिएआसियानवार्ता भागीदारों के साथ हमारी बातचीत को आगे बढ़ाएगा और उन्हें हमारे साथ आगे जुड़ने के लिए और हमारे इसक्षेत्र की शांति , स्थिरता और विकास के साझा लक्ष्य के लिए साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस संबंध में, सामान्य तौर पर आसियान और विशेष रूप से वियतनाम सदा ही भारत को बड़े सम्मान के साथ और एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप

में देखते हैं। अपने आकार , अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व मंच पर अधिक से अधिक भूमिका निभाने की इच्छा के आधार पर भारत की स्वाभाविक रूप से हिंद-प्रशांत में दुर्जेय स्थिति में है।

आर्थिक रूप सेएक आर्थिक महाशक्ति और एक प्रमुख वाहक के रूप मेंभारत बहुत लाभकी स्थिति में है। इसकी आबादी , एशिया में कामकाजी उम्र के उच्चतम अनुपात के साथ अपने युवाओं की जीवन शक्ति देश को आईटी का एक रचनात्मक केंद्र बनाती है। आसियान और अन्य देशों के साथ एफटीए और पीटीए की बढ़ती वेब के माध्यम से देश क्षेत्रीय विकास में योगदान कर सकता है और एशिया के बाकी हिस्सों के साथ निवेश के दोतरफ़ा प्रवाह को बढ़ा सकता है।-

रणनीतिक रूप सेभारत एक पूर्व और पश्चिम के बीच भूमि और समुद्री स्थान का विस्तार करने वाली एक भू-राजनीतिक स्थिति में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक और अग्रणी सदस्य के रूप मेंयहदेश विकासशील दुनिया में उच्च प्रतिष्ठा और भूमिका रखता है। भारत और अन्य शक्तियों के साथ उसके संबंधों ने लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना का एक घटक बनाया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत वैश्विक महत्व और प्रभाव वाले नेताओं में से एक साबित हो रहा है।

पिछले दो दशकों मेंभारत ने आर्थिक सहयोग और सुरक्षा पहलों के माध्यम से अपनी उल्लेखनीय लुक ईस्ट नीति के साथ रचनात्मक भूमिका निभाई है। 2012 में शांति और साझा समृद्धि के लिए आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थापना ने हमारे सहयोग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में आपकी उपस्थिति कई क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है , ये क्षेत्र हैं: राजनीतिक , आर्थिक, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सहयोग। आंकड़े ही प्रभावशाली हैं: भारत और आसियान के बीच वस्तु संबंधी मुक्त व्यापार समझौते ने 1.8 बिलियन उपभोक्ताओं के साथ दो विशाल बाजारों के बीच एक संबंध बनाया है और कुल 3 ट्रिलियन अमरीकी डालर का जीडीपी आउटपुट है। भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार की प्रमात्रा 2012 में 80 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई।

हालांकि, आसियान और भारत के बीचअभी भी संभावनाएं हैं जिन्हें दोहन करने और आगे खोज करने की आवश्यकता है। हमें साथ मिलकर अंतर क्षेत्रीय पहल में काम करने की जरूरत है। हमें- गंगा पहल जैसे हमारे उप- के बीच मेक (सार्क) आसियान और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्षेत्रों को जोड़ने वाली योजनाओंपर बल देने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतसार्थक तरीके से मदद कर सकते हैं , जैसे किनिम्न मेकांग जिसके लिए जापान , संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया सहयोग कर रहे हैं, और बुनियादी ढाँचे, भूमि और समुद्री परिवहन में कनेक्टिविटी के लिए पहल।

हम आसियान में देखते हैं कि हाल के वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के हितों में वृद्धि हुई है। मैं दस दिन पहले अंतिम संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में आसियान भारत कनेक्टिविटी के लिए समन्वय- समिति की स्थापना का स्वागत करता हूं।आसियान-भारत केन्द्र कीभी हाल ही में स्थापना की गयी थी , लेकिन कुछ नई पहलों के साथ।

संक्षेप में, हम आसियान में भारत की प्रतिबद्धता और ठोस उपायों के साथ आसियान के साथ जुड़ाव का स्वागत करते हैं। हम सभी दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति को राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी अधिक देखना चाहते हैं। और आसियान के एक जिम्मेदार और सक्रिय सदस्य के रूप मेंवियतनाम भारत और इस संघ के बीच सहयोग के लिए सबसे आगे रहने के लिए तैयार है। आसियान के सहयोग से और भी अधिक सक्रिय भारत के साथ , हम एक विशाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत लिंकेज, कुशल कनेक्टिविटी और आखिरकार, साझा समृद्धि और शांति के साथ देख सकते हैं।

3. बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में वियतनाम-भारत रणनीतिक साझेदारी

इस तीसरे प्रश्न पर मैं क्यों आया : हम, वियतनाम और भारत इस बदलते परिदृश्य में साथ मिलकर क्या कर सकते हैं ?

वियतनाम और भारत के बीच संबंध का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय सभ्यता ने वियतनामी संस्कृति में अपने दृश्यमान और अदृश्य निशान छोड़े हैं। हमारे दोनों देशों के बीच इस समय सम्मानित बातचीत की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही है।

1945 में आधुनिक वियतनाम की स्थापना के साथहमारे पास एक वफादार मित्र के रूप में भारत रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप हम में भी ऐसा ही पाएंगे। लगातार और वर्षों से निर्मित , आपसी विश्वास सबसे महत्वपूर्ण विरासत है जो हमारे पास है। और यह बहुत ही आपसी विश्वास था जिसने अशांति के समय में हमारी पारंपरिक मित्रता को बनाए रखने में मदद की। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विरासत है जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। और मैं निश्चित हूं कि स्वर्गीय राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और दिवंगत प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे बनाए रखना चाहते थे।

आपसी विश्वास, सामान्य मूल्यों और साझा रणनीतिक हितों की नींव पर , वियतनाम और भारत के बीच सामरिक साझेदारी 2007 में बनी और तब से यह फल फूल रही है। इस समय भी जबकि चुनौतियां कम नहीं है, हमें बदलते क्षेत्रीय संदर्भों द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति और समग्र अंतराष्ट्रीय एकीकरण की वियतनाम की विदेश नीति के बीच संबंध हमें एक साथ काम करने के लिए बहुत जगह प्रदान करती है। हमें द्विपक्षीय सहयोग में विशाल क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिए अपना सामूहिक प्रयास करना चाहिएताकि हमारी साझेदारी एक मजबूत जमीन पर खड़ी हो।

2007 में हमारे दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी संबंधी घोषणा पत्र ने सहयोग के पांच स्तंभों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया। ये हैं: राजनीतिक , रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग और

वाणिज्यिक सहयोग , निकट व्यापार और निवेश , विज्ञान और प्रौद्योगिकी , सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग तथा बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग। 2011 में भारत की अपनी राजकीय यात्रा के दौरानराष्ट्रपति ट्रुओंग सांग सेंग और भारतीय नेताओं ने और अधिक ठोस कदमों और लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की, जिन पर दोनों पक्षों को काम करना चाहिए। उनमें से नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि हमें 2015 तक वार्षिक दो-तरफा व्यापार को 7 बिलियन अमरीकी डालर तक लाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

2012 के अंत तकहमने सफलतापूर्वक वियतनाम और भारत की दोस्ती के एक वर्ष को निभाया। वर्ष के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रयासों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कींजो आने वाले वर्षों में हमारे संबंधों के लिए मजबूत आधार बना।

वर्ष 2013 में हमने पिछले वर्ष जो कुछ हासिल किया है, उसे समेकित करने के लिए और अधिक प्रयास किए हैं। पिछले हफ्तेभारतीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महामहिम श्री कपिल सिब्बल ने वियतनाम का दौरा किया और अपने वियतनामी समकक्ष के साथ कई समझौते किए। आगामी वर्षों में , वियतनाम नए विकास मॉडल के लिए एक नींव के रूप में आईटी का चयन करेगा। हम मदद और समर्थन के लिए भारत को दुनिया में एक प्रमुख आईटी उद्योग के पावरहाउस के रूप में देखते हैं। मैं मंत्री सिब्बल के प्रस्तावों से पूरी तरह सहमत हूं कि वियतनाम और भारत को आईटी में संयुक्त उपक्रम स्थापित करना चाहिएजिससे भारत के सॉफ्टवेयर और वियतनाम के हार्डवेयर उत्पादों में पूरा लाभ हो सके।

इस बार भारतीय गणतंत्र की मेरी यात्रा मेरे सहयोगीविदेश मंत्री महामहिम श्री सलमान खुर्शीद , के साथ संयुक्त वियतनाम - भारत आयोग की 15 वें सम्मेसलन में सह-अध्यकक्षता करने से संबंधित है। कल मंत्री खुर्शीद और मैंने अपने दोनों देशों के बीच कई लक्ष्यों को महसूस करने के तरीकों पर चर्चा की। मैंने अपने विचार व्यक्त किए कि वियतनाम के पास व्यापार के निवेश के मामले में बहुत कुछ है। हम तेल की खोज, बिजली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कृषि में अधिक अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय व्यवसायों की सहायता करते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि टाटा पावर को सोक ट्रांग प्रांत में थर्मल पावर प्लांट लॉन्ग फु 2 का निर्माण करने के लिए 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ठेका मिला है , इस प्रकार भारत को वियतनाम के 40 वें से 12 वें सबसे बड़े विदेशी निवेशक के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है।

ये हमारे हाल के प्रयासों के कुछ उदाहरण हैं। जितना मुझे अपनी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती पर गर्व है , मैं अपने संबंधों की संभावना को लेकर पूरी तरह आशान्वित हूं। संभावनाएं हैंऔर ये संभावनाएं विशाल हैं। मायने यह रखता है कि हमें उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए साथ मिलकर अथक प्रयास करते रहना चाहिए।

देवियों और सज्जनों,

मैंविश्व मामलों की भारतीय परिषद के आप सभी विद्वानों और अधिकारियों के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। कृपया आश्वस्त रहें कि हम वियतनाम में आपके शोध, बहस और नीति सिफारिशों का बारीकी से पालन करते हैं। हम वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति और हमारी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर आपके इनपुट को बहुत महत्व देते हैं।

राजदूत राजीव भाटिया , देवियों और सज्जनों आपको बेहतर स्वास्थ्य , खुशी और समृद्धि की शुभकामनाएं।

एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

*****